

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28 मई, 2021

विषय:—श्री केदारनाथ धाम में यात्रा/पूजा के सफल संचालनार्थ आधार भूत संरचना हेतु कुल-3812.92 वर्ग मीटर आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2288/KDA(2019-2020), दिनांक 19 फरवरी, 2021 तथा पत्र संख्या-3366/KDA(2019-2020), दिनांक 08 अप्रैल, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री केदारनाथ धाम में यात्रा/पूजा के सफल संचालनार्थ आधार भूत संरचना हेतु ग्राम केदारनाथ पटवारी क्षेत्र फाटा, तहसील ऊखमीठ, जनपद रूद्रप्रयाग की नॉनजेडए की खाता खतौनी संख्या-02 में प्लॉट नम्बर 1,2 एवं 3 के खसरा नम्बर 49, 50 एवं 56 में कुल 3812.92 वर्गमीटर भूमि देवस्थानम् बोर्ड के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आख्या/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री केदारनाथ धाम में यात्रा/पूजा के सफल संचालनार्थ आधार भूत संरचना हेतु ग्राम केदारनाथ पटवारी क्षेत्र फाटा, तहसील ऊखमीठ, जनपद रूद्रप्रयाग की नॉनजेडए की खाता खतौनी संख्या-02 में प्लॉट नम्बर 1,2 एवं 3 के खसरा नम्बर 49, 50 एवं 56 में कुल 3812.92 वर्गमीटर भूमि जिसका मूल्य रु० 43,10,032.10/- (तैतालीस लाख दस हजार बत्तीस रु० 10 पैसा मात्र) होता है, को शासनादेश सं०-258/16(1)/73-राजस्व-1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1, दिनांक-12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या-496/XVIII(II)/2020-8(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदया उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् प्रबन्धन बोर्ड के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

- 2- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दिनांक 9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- 6- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85 (24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- 8- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 9- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- 10- भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
- 11- संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3- कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

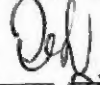
(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या-470(1)/XVIII(II)/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् प्रबन्धन बोर्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- ✓ 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।